ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 34-38
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-8, No.-II, Issues-IX YEAR- Dec-2017

ग्रामीण क्षेत्र में जातीय व्यवस्था का एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन

(चित्रकूट के क्षीर ग्राम पंचायत के विशेष सन्दर्भ में)

1. राजेश त्रिपाठी 2. आराधना ओझा''

1. एसो0 प्रोफे0, 2. शोधअध्येत्री

समाजशास्त्र, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, (म0प्र0) भारत

जाति एक वंशगत अंतर्विवाही और सामान्यतः स्थानीय समूह है। जातियों में परस्पर पाम्परिक संबंध होते हैं और स्थानीय अधिक्रम में इनका एक विशिष्ट स्थान होता है। जातियों के बीच संबंध अपवित्रता तथा शुचिता की संरचना द्वारा नियंत्रित होते हैं। जाति व्यवस्था धार्मिक आधार पर अंतर्निहित होती है। इसे वंशानुक्रम अंतर्जातीय और तय मानदंड़ों वाले समूहों का वर्ग समझा जा सकता है।

प्रस्तुत लेख में ग्रामीण जाति व्यवस्था की वर्तमान समय की वास्तविक परिस्थितियों का चित्रण–विभिन्न आधारों पर शोध के माध्यम से किया गया। इनमें जाति, व्यवसाय, जाति व्यवस्था के स्थान पर अन्य वांछित व्यवस्था (वर्ण, वर्ग, समाजवादी) जाति व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप, जातिवाद उत्पन्न होने के कारण, जाति व्यवस्था के भविष्य, जाति व्यवस्था में सुधार आदि विषयों पर स्थिति का वर्णन किया गया।

जाति व्यवस्था हिंदुओं के सामाजिक जीवन की विशिष्ट व्यवस्था है, जो उनके आचरण, नैतिकता और विचारों को सर्वाधिक प्रभावित करती है। यह व्यवस्था कितनी पुरानी है इसका उत्तर देना कठिन है। जाति (कास्ट) शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया है जिसका अर्थ नस्ल (रेस) या वंश या कुल (प्योर स्टॉक) होता है। भारत में जाति व्यवस्था को व्यक्त करने के लिए कोई एक शब्द नहीं है। भिन्न–भिन्न शब्द इस व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त करते हैं। प्राचीन ग्रामीण समाज एक ऐसे समाज के अन्तर्गत आता है जहाँ पर समस्त सामाजिक कार्यों पर परम्पराओं एवं रूढ़ियों का नियंत्रण होता था। ग्रामीण समाज के अन्तर्गत पारिवारिक विवाह आदि एक प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के रूप में कार्य करती थी, जो कि समस्त सामाजिक जीवन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करती थी।

ग्रामीण समाज : ग्रामीण समाज मुख्य रूप से एक कृषिप्रधान समाज होता है। वहाँ पर जाति व वर्ग के आध ाार पर कार्यों का व व्यवसायों का विभाजन किया जाता है। मुख्यतः ग्रामीण समाज हर वर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का कार्य पूजा–पाठ व विद्या से संबंधित क्षत्रियों का कार्य सामाजिक या गाँव की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना व वैश्यों का कार्य व्यवसाय करना तथा अन्त में शूद्रों का कार्य समाज के सभी वर्ग की सेवा करना था। ग्रामीण समाज में शिक्षा का स्तर काफी संकुचित था अर्थात् इससे सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के लोग ही शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। स्त्रियाँ पुरुषों की तरह यज्ञ व अन्य सामाजिक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती थी व इनको समाज में सम्माननीय अधिकार प्राप्त थे। अतः वैदिक काल में ग्रामीण समाज अपने सम्पूर्ण विकास की ओर अग्रसर था।

जाति व्यवस्था : जाति प्रथा ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है, यह हिन्दुओं में सामाजिक संगठन की प्रमुख विशेषता रही है। जाति के अध्ययन के बिना हम सामाजिक संस्थाओं के मूल रूप को नहीं समझ सकते। भारत में जाति ही व्यक्ति के कार्य, प्रस्थिति उपलब्ध अवसरों एवं असुविधाओं को तय करती है। ए.आर.देसाई का मत है, कि जाति प्रथा गाँवों में पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन प्रणालियों, उनके निवास स्थानों तथा सांस्कृतिक प्रतिमानों को निश्चित करती है। भूस्वामित्व भी जाति पर आधारित है। अनेक कारण वश प्रशासकीय कार्यों को अधिकांशतः जाति के आधार पर बांटा गया है। जाति के लोगों के जटिल आर्थिक और लौकिक सांस्कृतिक प्रतिमानों को भी निर्धारित किया है। इसने विभिन्न समूहों के मनोविज्ञान को स्थापित किया है और सामाजिक तथा ऊँच–नीच सम्बन्धों के ऐसे सूक्ष्म क्रमबद्धस्तर स्थापित किये हैं कि सामाजिक संरचना एक विशाल श्रेणियों में विभक्त स्तूप की भाँति दिखलाई पड़ती है। जिसका आधार, स्थल अछूत जनसमूह है और जिसका शिखर कुछ ब्राह्मणों द्वारा निर्मित है। हिन्दू समाज में हमें अनेक विशिष्ट और आत्मनिर्भर जाति समूह देखने को मिलेंगे।

जाति व्यवस्था का इतिहास : पूर्व औद्योगिक समाजों में जाति व्यवस्था विशेषतः पायी जाती है। जैसे–जैसे कोई समाज औद्योगीकरण की दिशा में आगे बढ़ता है। उसके साथ–साथ वहाँ गति विभाजन के बजाय वर्ग विभाजन का महत्व बढ़ता जाता है। परम्परावादी एवं कृषिप्रधान समाजों में जाति व्यवस्था का विशेषतः प्रभाव देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था में सामाजिक विषमता को धर्म के द्वारा समर्थन प्राप्त होता है, भारतीय जाति व्यवस्था को धर्म एवं प्रथागत कानून दोनों ही रूपों में समाज द्वारा स्वीकृत रही है। जाति व्यवस्था के अन्तर्गत पाया जाने वाला ऊँच–नीच का संस्तरण तथा

अनुरूपी लेखक

उच्च व निम्न जातियों के बीच अधिकारों का असामान्य वितरण भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक विषमता के लिये विशेष उत्तरदायी है। सामाजिक विषमता का चरम रूप अस्पृश्यता के रूप में वहाँ देखने को मिलता है। जहाँ कुछ जातियों को जन्म से ही अछूत मान लिया जाता है तथा उच्च जातियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले सब प्रकार के अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया जाता है। उच्च जातियाँ उत्पादन के साधनों के विशेषतः भूमि पर नियंत्रण रहा है, जबकि निम्न जातियों या अस्पृश्य जातियों के लोगों को इससे वंचित रहना पड़ा है। वे केवल अपने श्रम को बेंचकर अथवा कोई घृणित या हीन समझे जाने वाले पेशों को अपनाकर ही अपनी आजीविका चलाते आ रहे हैं।

ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था : भारतीय ग्रामों में जाति सामाजिक संगठन की आधारशिला है। वह आज भी एक महान शक्तिशाली संस्था है। जाति गाँवों में व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार को तय करती है। अनेक विद्वानों ने ग्राम एकता के स्थान पर जाति के अस्तित्व का ही उल्लेख किया है। जाति में ग्रामों के विभिन्न पक्षों के साथ सम्बन्ध पाये जाते हैं। ग्रामीण आर्थिक जीवन जाति द्वारा अल्पाधिक प्रभावित है। आर्थिक जीवन के विभिन्न पक्षों के आधार पर जातीय प्रभाव को स्पष्टता से देखा सकता है। जैसे–उत्पादन, उपभोग, ऋणग्रस्तता, निवास, गतिशीलता आदि।

जाति एवं संयुक्त परिवार ग्रामीण जीवन को प्रभावित करने वाली दो मुख्य संस्थायें है। ये दोनों संस्थायें ग्रामीणों के सामूहिक जीवन कार्यकलापों, आदर्श व्यवहारों और मूल्यों, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति एवं विचारधारा को निर्धारित करती है। ये दोनों संस्थायें परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती है। संयुक्त परिवार में जातीय नियमों का कठोरता से पालन कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में जाति सामान्यतः संयुक्त परिवारों का एक झुण्ड है। इसलिये जाति का परिवारों के जीवन को एक विशिष्ट ढांचे में ढाल देती है।

आधुनिक ग्रामीण भारत पर जाति व्यवस्था का बदलता स्वरूप :जातिगत पेशा गाँवों में प्रारम्भ से ही प्रचलित था। वैदिक मान्यताओं के आधार पर जातियाँ मुख्य रूप से चार भागों में बाटी गयी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कर्मकाण्ड और मुख्यतः शिक्षा से जुड़े थे। क्षत्रिय समाज की रक्षा करता था। वैश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था से और शूद्र सेवा करता था। समय–समय पर इसमें विकृतियाँ आती रही है। जैसे–ब्राह्मण अपने ज्ञान के आधार पर पूरे समाज में कर्मकाण्ड को प्रभावी बना दिया जिससे एक अजीवों गरीब संरचना निर्मित हो गयी और बिना इसे पूरा किये उद्वार हो पाना लगभग असम्भव सा बन गया। सबसे बड़ी बाधा इस कर्मकाण्ड में वह थी कि शूद्रों के लिए भी यह व्यवस्था अनिवार्य थी। परन्तु छुआछूत के चलते इन्हेंयह कार्य अपने स्तर पर सम्पादित करना होता था। उच्च जातियाँ इनके कार्य में शरीक नहीं होती थी।

जाति प्रथा का भविष्य : जाति ने सामाजिक एकता की स्थापना की है। जाति व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करती है। जाति अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। जाति जन्म से ही अपने सदस्यों का व्यवसाय निश्चित कर देती है, परन्तु जाति प्रथा दोषों से मुक्त नहीं है। वर्तमान युग में जाति प्रथा में होने वाले परिवर्तनों को देखकर लोगों को जाति प्रथा के भविष्य के सम्बन्ध में चिन्ता हो गयी है। जाति व्यवस्था के दाषों को देखकर कुछ लोग जाति व्यवस्था के उन्मूलन के पक्ष में हैं।

अतः इस विषय की गम्भीरता से अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे कि सम्पूर्ण ग्रामीण समाज में सामाजिक सहयोग एवं समरसता को बनाये रखा जा सके। प्रस्तुत अध्ययन इसी में किया गया एक प्रयास है।

उद्देश्य :

1. उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक, परिस्थितियों का अध्ययन करना।
2. भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में जाति व्यवस्था की वर्तमान स्थिति का आंकलन करना।
3. भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों के कारणों को ज्ञात करना।
4. ग्रामीण क्षेत्र में जातिवाद एवं इसके प्रभावों का आंकलन करना।
5. जाति व्यवस्था में सुधार हेतु उत्तरदाताओं से सुझाव प्राप्त करना।

अध्ययन क्षेत्र : इस अध्ययन हेतु क्षीर, नगर पंचायत का चयन किया गया है। ग्राम क्षीर, जिला–सतना, मध्यप्रदेश में रामघाट चित्रकूट के पास स्थिति है जो रामघाट से लगभग 2 किलोमीटर पूर्व की ओर बसा है।

शोध पद्धतिः क्षीर नगर पंचायत में कुल परिवारों की संख्या 86 है। प्रस्तुत शोध हेतु समस्त परिवारों से 50 परिवारों का चयन सोउद्देश्य निदर्शन पद्धति से विभिन्न जाति एवं धर्म से सामाजिक तथा आर्थिक स्तर से किया गया है।

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-8, No.-II, Issues-IX YEAR- Dec-2017

सारणी क्रं. 01 : जाति के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	जाति	संख्या	प्रतिशत
1	सामान्य	02	04.00
2	पिछड़ी जाति	41	82.00
3	अनुसूचित जाति	07	14.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	00.00
	योग	50	100

अतः स्पष्ट है कि गाँव में ग्रामीण जाति व्यवस्था की परिचर्चा में सर्वाधिक भाग पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों ने लिया।

सारणी क्रं. 02 : व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1	मजदूरी	19	38.00
2	कृषि	16	32.00
3	व्यापार	08	16.00
4	नौकरी	07	14.00
	योग	50	100

अतः स्पष्ट है कि गाँव में सर्वाधिक उत्तरदाता मजदूरी एवं कृषक वर्ग के पाये गये।

सारणी क्रं. 03 : जाति व्यवस्था के स्थान पर अन्य वांछित व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	अन्य व्यवस्था	संख्या	प्रतिशत
1	वर्ण व्यवस्था	08	16.00
2	वर्ग व्यवस्था	10	20.00
3	समाजवादी व्यवस्था	09	18.00
4	नहीं चाहते	18	36.00
	योग	50	100

अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता जाति व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे चलाना चाहते हैं।

सारणी क्रं. 04 : जाति व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	अच्छी	18	36.00
2	खराब	08	16.00
3	मध्यम	23	46.00
4	बहुत अच्छी	01	02.00
5	बहुत खराब	00	00.00
	योग	50	100

अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार गाँवों में जाति व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप मध्यम है।

सारणी क्रं. 05 : गाँव में जातिवाद उत्पन्न होने के कारण के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1	आपसी स्वार्थ	31	62.00
2	राजनीति जागरुकता	07	14.00
3	राजनीतिक हस्तक्षेप	12	24.00
4	अन्य	00	00.00
	योग	50	100

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-8, No.-II, Issues-IX YEAR- Dec-2017

अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता आपसी स्वार्थ को जातिवाद उत्पन्न होने का प्रमुख कारण मानते हैं, जिसका कारण है कि लोग अपने हितों को अधिक महत्व देने लगे हैं।

सारणी क्रं. 06 : जाति व्यवस्था के भविष्य के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	जाति व्यवस्था का भविष्य	संख्या	प्रतिशत
1	समाप्त हो जायेगी	18	36.00
2	और मजबूत होगी	13	26.00
3	संकटकालीन स्तर से गुजरेगी	19	38.00
	योग	50	100

अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता जाति व्यवस्था को संकट में देख रेख है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

1. अध्ययन क्षेत्र में 82 प्रतिशत पिछड़ी जाति के उत्तरदाताओं ने जाति व्यवस्था के प्रति अधिक रुचि दर्शायी, क्योंकि संख्या में यही लोग शोध क्षेत्र में अधिक निवास कर रहे हैं।
2. शोध क्षेत्र में अधिकांश उत्तरदाता कृषि कार्य एवं मजदूरी व्यवसाय में लिप्त पाये गये।
3. ग्राम में अधिकांश 36 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो जाति व्यवस्था के स्थान पर अन्य कोई व्यवस्था नहीं चाहते हैं।
4. ग्राम में 86 प्रतिशत उत्तरदाता जाति व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप को मध्यम रूप में स्वीकार कर रहे हैं।
5. गाँव में सर्वाधिक 62 प्रतिशत उत्तरदाता जातिवाद उत्पन्न होने का प्रमुख कारण आपसी स्वार्थ मानते हैं।
6. गाँव में 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि जाति व्यवस्था संकटकालीन स्तर से गुजरेगी।
7. गाँव में 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि जातिवाद दूर करने का प्रमुख उपाय शिक्षा का प्रसार है।

सुझाव :

1. सभी जाति के लोगों को गाँव से जातिवाद को समाप्त करने के लिए लिए समान रूप से पहल करने की आवश्यकता है।
2. ग्राम में प्रौढ़ शिक्षा एवं अन्य शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रसारित करने की आवश्यकता है।
3. कृषकों एवं मजदूरों को जागरुक करने के लिए जागरुकता रैली एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना उचित होगा।
4. सभी जातियों में आपसी एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाना आवश्यक है।
5. आपसी स्वार्थ को मन से हटाकर जागरुकता, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध एवं सहयोग की भावना रखना आवश्यक है।
6. सभी लोगों को ऊँच–नीच की भावना का त्याग एवं जाति व्यवस्था संबंधी समस्याओं के निदान का प्रयास करने की आवश्यकता है।
7. जातिवाद को समाप्त करने एवं जाति व्यवस्था में सुधार करने के लिए लोगों की इच्छा के अनुरूप शिक्षा के प्रसार का भरपूर प्रयास करना उचित होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. तेज संगीता एवं पाण्डेय ओजस्कर, 2011, समाजकार्य के क्षेत्र, भारत प्रकाश, अशोक मार्ग, लखनऊ
2. डॉ. राजेश त्रिपाठी एवं त्रिभुवन सिंह, 2002, स्वस्थ्य समाज की ओर, ग्राम स्वराज संस्थान, पन्ना, मध्य प्रदेश, प्रथम संस्करण
3. डॉ. गुरुदेव उपाध्याय, 2001, ग्रामीण विकास एवं प्रबन्धन, बी.एस.शर्मा एण्ड ब्रदर्श, 132 बालाजी पुरम, शाहगंज, आगरा–10.
4. ए.आर.देसाई, ग्रामीण समाज
5. रवीन्द्रनाथ मुखर्जी, सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध, सरस्वती सदन–7, यू.एस.जवाहर नगर, दिल्ली

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-8, No.-II, Issues-IX YEAR- Dec-2017

पत्र, पत्रिकाएँ एवं जर्नल्स :

1. कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली
2. प्रतियोगिता दर्पण
3. समाज कल्याण, नई दिल्ली

*****